MCM-HK/2P/5.00

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : तमिलनाडु में भी एक चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबको इस चीज का ज्ञान है। अभी उत्तर भारत में बचे हुए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि आप नेताओं को कैसे करप्ट मानकर चल रहे हैं। कम से कम इसको तो बंद करिए और अगर बंद नहीं करेंगे तो जग हंसाई हम सब की होगी। मुझे खुशी है कि मैंने एम0पी0 सैलेरी का मामला उठाया था। चलिए, आपने एम0पीज़0 को पहली तारीख से कुछ देने को कहा। मैं कहूंगा कि मीडिया वालों की भी कुछ मदद कर दीजिए। इनके मालिक इनका बहुत शोषण कर रहे हैं। एक कानून इनके लिए भी ला दीजिए, कम से कम वे हमारे साथ तो खड़े हो जाएं। दिन भर दौड़ते हैं हमारे और शाम को निकल लिए। इनकी कांट्रेक्ट सर्विस चल रही है। इनको भी सुरक्षा दे दीजिए, इनकी भी तनख्वाह फिक्स कर दीजिए। हमारे लोक सभा के एक एम0पी0 थे, उन्होंने स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दी, हैं तो वे हमारे भतीजे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उसमें बड़ी आदर्शवादिता थी। ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान के हर आदमी का स्विट्ज़नरलैंड में एकाउंट है, ऐसा लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में हम सब का एकाउंट है। जो लोग गोल्डन स्पून इन दि माउथ पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों की हालत नहीं मालूम। आप इनको सिखाइए कि राजनीति में कितना त्याग और तपस्या करके आदमी आता है। परिवार के नाम पर तो बहुत लोग जीत जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जमीन से राजनीति में जुड़े होते हैं। मैंने आज वह भी स्थिति देखी है कि तमाम एम0एल0एज़0, तमाम एम0पीज़0 चाय की दुकान चला रहे हैं अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए। उनके पास जमीन नहीं है

खेती करने के लिए। हमारे हरदोई में एक एक्स एम0पी0 हैं, उनका बेटा पुताई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है। वे दो टर्म्स एम0पी0 और 5 टर्म्स एम0एल0ए0 रहे थे। उनकी हालत तो देख लीजिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि एक्स एम0पीज़0 को भी आप कुछ राहत दे दीजिए, वह ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमसे कहा है कि एक दिन तो सब को एक्स होना है। परमानेंट कौन है? अभी गुलाम नबी जी कह रहे थे कि परमानेंसी कोई मत समझिएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह गए, हो सकता है कल आप ही आ जाओ। हो नहीं सकता, आ ही रहे हैं हम। नीचे की जो स्थिति है, वह स्थिति आने वाली है।.....(व्यवधान).....

काला धन और उसके नाम पर आपने देश से एकदम भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया और आज स्थिति यह हो गई है कि आप खान मार्केट चले जाइए, कनाट प्लेस चले जाइए, बड़े-बड़े घरों के लड़के फटी पेंट पहन रहे हैं और फटी हुई टीशर्ट पहन रहे हैं। अगर उनकी यह हालत होगी तो गरीबों की क्या हालत होगी? एक जमाने में फटी पेंट बर्तन वाले ले जाते थे। अगर हमारे देश की हालत यह हो गई कि बड़े-बड़े घर के लड़के फटी पेंट पहनने लगे.....(व्यवधान).....

महोदय, दिल्ली में सीलिंग के विरोध में तीन दिन से बाजार बंद हैं। आप पार्टी वाले बैठे हुए हैं संजय भाई और दोनों गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है कि आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिल रही। आपने मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान से एक महीने बाद कुछ राहत मिलेगी। तब तक दिल्ली का बाजार बरबाद हो जाएगा, व्यापारी क्या करेगा? अगर उसके हाथ में कटोरा

पकड़ाने की आपकी योजना है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे याद है पिछले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जी आए थे, कहने लगे नरेश जी, इस बिल को अभी पास करा दीजिए, नहीं तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा। हम लोगों ने समझा कि बिल पास करा दिया तो दिल्ली ठीक हो गई, लेकिन आज इतनी समस्या है तो उसका समाधान तुरन्त क्यों नहीं करते? यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि देश में किसी के लिए मजबूरी होती है।

(2Q/SC पर जारी)

SC-DPS/5.05/2Q

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : जो आरएसएस वाले प्रचार करते हैं कि मोदी का विकल्प क्या है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक ज़माने में नेहरू जी का भी विकल्प कोई नहीं था, इंदिरा जी का भी विकल्प कोई नहीं था और राजीव गांधी जी का भी विकल्प कोई नहीं था, लेकिन इस देश में विकल्प बने हैं। इस देश का विकल्प जनता बनाती है। आप यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपके संगठन की वजह से आपको वोट मिले हैं। यह मीडिया और इनकी देन है। अम्बिका सोनी जी यहां बैठी हैं, ये सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। मैंने सेंट्रल हॉल में इनसे कहा कि अम्बिका जी, यह मीडिया आपके खिलाफ क्या-क्या प्रचार कर रहा है, आप मंत्री हैं, आप इसको रोकिए। इन्होंने कहा, मैं क्या कर सकती हूं? मैंने इनसे कहा कि आप मेरी यूथ की अध्यक्ष रही हैं और आप ऐसी बातें मुझसे कह रही हैं? आप हमें एक हफ्ता बिठा दीजिए और ये मीडिया वाले जो हम कहें, वह लिखते हुए न दिखायी दें तो कहें। आज यह सरकार वही नहीं

कर रही है। वह जो चाहती है, मीडिया लिख रहा है और जो वह चाहती है, वही मीडिया कहेगा। दिन भर मीडिया इनकी प्रशंसा करता है। एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में अगर एक बलात्कार हो जाता था या एक लूट की घटना हो जाती थी तो हमारी अक़लियत सरकार के खिलाफ मीडिया इतना चलाता था कि लगता था हिन्दुस्तान में हाला-डोला आ गया, भूकंप आ गया - उसे गांव में हाला-डोला कहते हैं - लेकिन आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट पूरा रुक गया है, उत्तर प्रदेश में फर्ज़ी encounter हो रहे हैं, एक-एक दिन में 37-37 मुठभेड़ें हो रही हैं, वहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कासगंज में खुले-आम तिरंगे झंडे के नाम पर जिस तरह से अराजकता फैलायी गयी, अगर आप उसकी आड़ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह गलतफहमी निकाल दीजिए। आपके कुछ नेता कर्नाटक में गए। उन्होंने कह दिया कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। ..(व्यवधान).. अब हमसे मत कहलाइए। अगर आप इन भाषणों को देश का सोच रहे हों..(व्यवधान)..

श्री तपन कुमार सेन : आपके अनंत हेगड़े साहब क्या कर रहे हैं?..(व्यवधान)..

श्री बी.के.हरिप्रसाद : वह अनंत कुमार नहीं, अनंतकुमार हेगड़े ने बोला है।..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल : लोकतंत्र के चार खंभे हैं। मैं कह रहा था कि अखिलेश जी की सरकार में मीडिया को सब कुछ खराब दिखता था, लेकिन आज वहां रोज रेप और अन्य चीज़ें हो रही हैं लेकिन उन्हें सब अच्छा दिखायी दे रहा है। देश में दो ही लोग चल रहे हैं - मोदी-मोदी और योगी-योगी, बाकी सब बेकार हैं। ऐसा लग रहा है देश में बाकी

कुछ रह ही नहीं गया है। ऐसे ही हमारे साथ भी था। जब emergency थी, हम यूथ कांग्रेस में थे, भाई साहब भी थे, सब थे। उस समय बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, सब तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है और इंदिरा जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम भी यंग थे, बड़ा अच्छा लगता था, अफसर सलामी देते थे, यूथ के अध्यक्ष थे, जिधर निकलते थे, मंत्री हम लोगों के पीछे होते थे लेकिन 1977 का चुनाव हुआ तो क्या हुआ? राजस्थान ने आपको alarm किया है। यह alarming situation है। आप सोच लीजिए, बहुत दिन नारों और जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। बहुत जुमले हो गए हैं, बहुत नारे हो गए हैं, देश को कुछ चाहिए। जो गुलाम नबी जी ने कहा, हमें वह भारत चाहिए, जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया बैठे, जहां हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक हों, जहां कहीं साम्प्रदायिकता न फैली हो। जहां जिस राम के नाम पर आप वोट ले रहे हैं, वह राम राज्य हमें दिखायी दे - हमें वह भारत चाहिए, हमें साम्प्रदायिकता का भारत नहीं चाहिए। आप अपनी यह सोच बदल दीजिए। आप गलतफहमी में मत रहिए। हिन्दू कभी साम्प्रदायिक नहीं होता। मैं यहां एक बात आपसे कह देता हूं कि किसी कौम को बहुत दिन डराकर रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैं हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बधाई दूंगा कि सबसे बड़ी आबादी अगर विश्व में मुसलमानों की कहीं है तो हिन्दुस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अगर कोई है तो वह हिन्दुस्तान है।

श्री आनन्द शर्मा : इंडोनेशिया के बाद दूसरा है।

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं। हमारे यहां 25 परसेंट जोड़ दीजिए, हम सबसे बड़े देश हैं, लेकिन यहां मुसलमान मिक्स्ड आबादी में रहता है। हिन्दू-मुसलमान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं।

(2आर-पीआरबी पर जारी)

PRB-KSK/2R/5.10

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत): हम एक दूसरे के घर शादी में जाएं, एक दूसरे के घर ईद में जाएं और वे होली में हमारे यहां आएं। यहां का मुसलमान शांत है। इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और यह आपको सोचकर चलना चाहिए। प्रजातंत्र के चार खम्भे हैं, आपने media अपनी जेब में कर लिया। जनता ने आपको बहुमत देकर बैठा दिया अब चाहे जिसको आप money bill कर दीजिए और हम लोगों की और राज्य सभा की जरूरत ही नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 110 में Money Bill का अधिकार आपको दे दिया है, जिसको चाहे आप उसको Money Bill कर दीजिए, तो यह लोक सभा और राज्य सभा भी बेकार हो गई, bureaucracy भी आपके कब्ज़े में है। अब judiciary के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जज खुले-आम आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज खुले-आम आरोप लगा रहे हैं और फिर उन्होंने मीडिया में कहा और मैं चाहता हूं कि इस सदन में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वे आरोप क्यों लगाए गए हैं? आखिर वे आरोप क्यों लगाए गए हैं? उन आरोपों का मतलब क्या है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के दबाव में उन जजों के खिलाफ social media में कहा गया है कि वे कांग्रेसी हैं ? अब social

media में यह भी चल रहा है, "नौकरियों पर पड़ा है हथौड़ा , बेचो चाय और तलो पकौड़ा"। यह आजकल social media पर बहुत तेजी से चल रहा है। आप सारे स्तम्भों को कब्ज़े में करते चले जा रहे हैं तो फिर प्रजातंत्र कहां रह गया है, यह तो तानाशाही का स्वरूप हो गया। Democracy जिंदा रखिए। यदि democracy जिंदा नहीं रखी तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा। इस सरकार ने अब तक विज्ञापन पर 3,755 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। गुलाम नबी जी कह रहे थे कि स्वच्छ भारत के ऊपर 550 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर खर्च किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर भी खर्च किए और योगा में सरकार के 450 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इतने रुपये में तो कोई योजना देश में दे देते उस गरीब का एक तो पिंड छूट जाता। किसान ख़ुदकुशी करके मर रहा है। किसान को आप क्या दे रहे हैं ? किसान तो ख़ुदकुशी कर रहा है। अभी मैं किसान पर आगे आऊंगा।

श्रीमन्, बजट आया। इन्होंने कहा कि यह बजट कृषि प्रधान बजट है। हर अखबार में मोटा-मोटा लिखा - चलो गांव की ओर, गांव का बजट। जैसे हमारी Under-19 team ने अभी New Zealand में Australia के खिलाफ जो World Cup जीता है तो एक अखबार ने लिखा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसा लगा कि जैसे क्रिकेट से ही पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। यहां राजीव शुक्ल जी बैठे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया कि सब क्रिकेट में ही कर दिया। इन्होंने देश में बाकी sports खत्म ही कर दिए। ऐसे ही सारे अखबारों ने लिख दिया कि चलो गांवों की ओर, गांव वालों को सब दे दिया। आपने गांव वालों को क्या दिया ? आज खाद लेनी हो तो अंगूठा लगाएं, बीज

लेना हो तो अंगूठा लगाएं, फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है। अगर आप डेढ़ गुने की बात करते हो तो गेहूं की MSP 1640 रुपये है। बाज़ार में एक महीने बाद गेहूं पक कर आ जाएगा, आप उसका दाम डेढ़ गुना घोषित कर दीजिए और उसे कार्यान्वित कीजिए। जैसे आपने Health Policy के बारे में कहा है कि यह अभी लागू होगी और फिर आप कहेंगे कि अक्टूबर-नवम्बर में लागू होगी। फिर आपने उसमें कह दिया कि 60% हमारा रहेगा, 40 % राज्यों का रहेगा। राज्यों की हालत यह है कि राज्यों का सारा development खत्म हो गया क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कर्जा माफी के नाम पर प्रदेश का सारा पैसा ही चला गया। अखिलेश जी ने तो सरकार के पैसे से तमाम सड़कें बनवा दीं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ पैसा ही नहीं रह गया। अगर आप राज्य सरकार से 40 प्रतिशत लेने की सोचेंगे तो कैसे मिल पाएगा ? मैं गुलाम नबी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ निजी insurance कंपनियों को फायदा देने के लिए प्रीमियम दिलवाया जाएगा। मेरी wife बीमार थी , मैं परसों उनको मैक्स अस्पताल से लेकर आया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपका हॉस्पिटल कितने लोगों को insurance की सुविधा देता है, तो उन्होंने कहा कि 1% भी नहीं देता।

(2S/GS पर जारी)

GS-GSP/2S/5.15

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : हम आज 60 साल की उम्र से ऊपर हैं और हम किसी इंश्योरेंस कम्पनी से अपना हैल्थ बीमा करवाने के लिए कहें, तो इंश्योरेंस कम्पनी हमारा

हैल्थ बीमा नहीं करेगी, क्योंकि हम 60 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं। हर आदमी को मेडिकल की जरूरत तो 60 साल की उम्र के बाद ही पड़ती है, उसके पहले तो वह हृष्ट-पुष्ट घूम ही रहा है, इसलिए उसको आपके हैल्थ बीमा की क्या जरूरत है? उसके पहले तो भगवान ने उसको हट्टा-कट्टा बनाया ही है और वह हट्टा-कट्टा घूम ही रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हैल्थ बीमा किसको दे रहे हैं? आप किसकी हैल्थ ठीक कर रहे हैं? आप 50 करोड़ लोगों को दो हजार करोड़ रुपये में पांच लाख रुपये तक का बीमा दे देंगे कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाएगा, तो उससे वहां पर पांच लाख रुपये तक का बिल नहीं लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप मेरे साथ कपड़े बदल लो और रात में किसी अस्पताल में मेरे साथ चलो। पहले वह इतनी जांच लिख देगा कि उसी में लाख-डेढ़ लाख रुपया चला जाएगा। कोई भी बिल दो-तीन लाख से कम का नहीं होगा और आप उससे कह दीजिए कि इसका पेमेंट बीमा कम्पनी से मिल जाएगा, तो वह आपको बंद कर लेगा। आजकल तो अस्पताल वाले बिना पेमेंट लिए डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। अब तो अपोलो जैसे अस्पताल डेड बॉडी रख लेते हैं और कहते हैं कि पहले पैसे दो। अब तो ऐसा भी नहीं है कि मरीज बेचारा मर गया है, तो उसकी डेड बॉडी को जाने दें।

उपसभापति महोदय, पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से आप नई पॉलिसी लाए हैं, तब से पेट्रोल के दाम 9 रुपये लीटर और डीजल के दाम 7 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। एक ज़माना था, जब हम लोग बजट को सुनते थे। हम बजट को इसलिए सुनते थे कि किस चीज़ के कितने दाम हो गए और वे दाम साल भर तक तो

रहेंगे। इंदिरा जी के समय में जब बजट आता था, तब यह होता था कि उसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे। अब तो बजट का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। मैं उस दिन अस्पताल में था, अखबारों ने बड़े जोर-शोर से लिखा कि डीजल और पेट्रोल दो रुपये सस्ता हुआ। मैंने कहा कि चलो कुछ तो असर हुआ, लेकिन अगले दिन पढ़ा कि उन्होंने दो रुपये सस्ता कहां किया, उन्होंने 6 परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी घटाई और 8 परसेंट सेस लगा दिया, तो उसकी कीमत तो उतनी ही रही। देश में कहां पर पेट्रोल, डीजल सस्ता हुआ है, देश में कौन-सी चीज़ सस्ती हुई है?

आप कहते हैं कि "उज्ज्वला योजना" में हम सबको रसोई गैस दे रहे हैं। आप जरा देख तो लीजिए कि उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है। कोई आदमी मुफ्त में रसोई गैस प्राप्त नहीं कर रहा है। उनको दो सिलेंडर की जगह एक सिलेंडर दिया जाता है और जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब वह 800 रुपये कहां से लाए कि वह अपने घर में सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके। यह वास्तविकता है और आप गांव की वास्तविकता देखिए।

हम कहते हैं कि हम सब पोलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यह ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इस कंट्री में सही है? जब हमारी योजनाएं ठीक से नीचे लागू नहीं होती हैं, तो सिस्टम को क्यों नहीं बदल दिया जाता है? हम क्यों अंग्रेजों के सिस्टम को रखे हुए हैं? जो आई.ए.एस. कहेगा, वही होगा। वे हमारे सामने आंकड़े इतने बढ़िया बनाकर ले आते हैं। अब डा. हर्ष वर्धन जी आ गए हैं, वे भी पर्यावरण को ठीक कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण की क्या हालत है? अमेरिका ने अपने यहां नागरिकों को चेतावनी दे

दी कि अब आप दिल्ली नहीं जाएंगे। यूनाइटेड एयरलाइन्स ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं। श्रीलंका की टीम मास्क पहनकर हमारे देश में खेलती है। इससे हमारी इमेज कितनी खराब हो रही है। हम अपने यहां का प्रदूषण क्यों नहीं ठीक कर सकते? आपने इतना सेस लगाया है, फिर भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। एक एन.जी.टी. बन गया है। अगर गांव का बेचारा किसान अपने खेत से मिट्टी निकालने जाए, तो शाम को उसको दरोगा बंद कर देगा। जंतर-मंतर पर इसी वजह से प्रदर्शन बंद कर दिए कि तुम्हारी आवाज़ न निकल सके। यह हमारा न्यू इंडिया है। आप पर्यावरण को ठीक करिए, हम सांस में ज़हर ले रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि सुबह टहलने मत जाना, क्योंकि टहलने से जितना फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली में डॉक्टर ऐसा कहता है। इससे तो हमारे छोटे गांव अच्छे हैं। कम से कम वहां पर प्रदूषण नहीं है और हमें साफ हवा मिल रही है।

हम रोज सुन रहे हैं कि सीमा पर हमारे सैनिक मर रहे हैं। मैं आज़ाद साहब से सहमत हूं कि कश्मीर इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब जाधव जी का मामला आया था, तब पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ था।

(HMS/2T पर जारी)

SK-HMS/2T/5.20

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : पूरे विपक्ष ने साथ दिया कि आप मजबूती से चलिए। सुषमा जी बोल रही थीं कि आप लोग कुछ comments मत करिए, यह international matter है। उस international matter में क्या हुआ? क्या जाधव की रिहाई हो गयी या

पाकिस्तान की जेलों में सैकड़ों बंद और हिंदुस्तानी, जिनका नाम पता नहीं मालूम, उनकी रिहाई हो गई? पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है। आपके 4 साल के शासनकाल में अब तक 800 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इतने तो युद्ध कर देते, तो भी शहीद नहीं होते और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होता। ..(व्यवधान).. surgical strike क्या थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री से बात नहीं करोगे, वहां के नेताओं से वार्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की सरकार मिलिट्री चलाती है। वहां आप चाहे साड़ी ले जाओ, चाहे बिंदी ले जाओ, उस से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कड़े होइए। चीन हमारा दुश्मन है, नेपाल हम से भागा जा रहा है, रशिया हमारा दोस्त था, लेकिन ट्रम्प के चक्कर में रशिया भी भाग गया वरना रशिया ने तो हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है। जब अमेरिकी बेड़ा आया था, तो रशिया ने अपना बेड़ा हिंदुस्तान की मदद के लिए भेजा था। यू0एन0ओ0 में अगर कोई देश हिंदुस्तान के पक्ष में वीटो करता था, तो सिर्फ रशिया करता था। आज चीन पाकिस्तान के पक्ष में वीटो कर रहा है। हम कहते हैं कि कह दो कि पाकिस्तान आतंकवादी है, तो चीन वीटो लगाता है कि नहीं ये आतंकवादी नहीं है। आप sanction नहीं लगा सकते। वहां कौन है, जो हमारे लिए वीटो लगाएगा, आप उसका नाम बता दीजिए? आपने कश्मीर में 9 हजार से अधिक पत्थरबाजों को छोड़ दिया। कल एक वीडियो वायरल हुआ है और सेना के जवानों के साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर देश की सेना demoralise हो जाएगी, तो देश खत्म हो जाएगा। हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना विश्व की सब से

अच्छी सेना है। हिंदुस्तान का कोई वीर सपूत कमजोर नहीं है, देश पर कुर्बान होने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जुमलों में कुर्बानी मत कराइए, जुमलों में बात मत करिए। यह देश एक मजबूत हिंदुस्तान चाहता है। आज चीन जिस तरह विश्व की महाशक्ति बन रहा है, आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी।

आपने एक nation एक election की बात कह दी। हम तैयार हैं, लेकिन योगी बाबा तैयार हैं कि नहीं? आप साल-दो साल बाद चुनाव करा लो - यू0पी0 में भी करा लो, गुजरात और हिमाचल के भी करा लो। यह कैसे होगा? जब तक आप Constitution में परिवर्तन नहीं करेंगे कि State Assembly पांच साल तक भंग नहीं होगी, तब तक one nation, one election कभी नहीं हो सकता। अगर Assembly भंग होगी, तो आगे चुनाव फिर बीच में होने लगेगा। अभी जैसे यहां President rule नहीं होता, वैसे स्टेट में भी कोई President rule नहीं हो। जब पांच साल तक चुनी हुई सरकार चलेगी, तभी आप one nation, one election की बात कर सकते हैं। मुझे याद है, इंदिरा जी के जमाने में मध्य प्रदेश से सेठी जी आते थे, उन्होंने अमेरिकन सिस्टम वाली बात चलायी और वह बहुत जोर से चली कि अमेरिकन सिस्टम पर हिंदुस्तान में चुनाव होने चाहिए यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो, बाकी के न हों।

श्री राजीव शुक्ल : वसंत साठे जी ने कहा था।

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर सेठी जी ने भी यह मुद्दा उठाया था।

श्री डी0पी0 त्रिपाठी : यह बात वसंत साठे जी ने शुरू की थी। ..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल : राजीव जी, जब मैं कांग्रेस में adult हो गया था, तब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होगे।

श्री राजीव शुक्ल : अभी आप ज्यादा adult हो गए हो, कभी-कभी भूल जाते हो।

श्री नरेश अग्रवाल : आपने काले धन की बात कही और नोटबंदी से हमें क्या मिला? आज तक रिजर्व बैंक बता नहीं पा रही है कि नोटबंदी से क्या मिला? उस बारे में फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि रिजर्व बैंक अभी तक कुछ बता नहीं पा रही है कि क्या हुआ? वे 99 परसेंट स्वीकार कर रहे हैं और हमें लगता है कि 101 परसेंट हो गया है क्योंकि नकली नोट कहां हैं? वे तो हैं ही नहीं। अभी कानपुर में 93 करोड़ रुपए पकड़े गए। पता नहीं, देश में ऐसा कितना धन होगा? पता नहीं, नेपाल हमें कितना रुपया देगा?

(2 यू/एएससी पर जारी)

ASC-YSR/5.25/2U

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : वे नेपाल से उसको white करना चाहते थे। आपने को-ऑपरेटिव बैंक से कितना लिया, अभी आपको पता नहीं है। अभी अमित शाह भी कह रहे थे कि हमने काला धन समाप्त कर दिया, तो कहां था कालाधान, जो सफेद कर दिया? ...(व्यवधान)... काला धन स्विटज़रलैंड बैंक में था। काला धन सिंगापुर, पनामा और दुबई में है। आपने विदेशों से काला धन लाने की बात की थी। आजकल सोशल मीडिया पर एक लिस्ट आई हुई है। उसमें आपकी पार्टी के सब लोगों के नाम दिए गए हैं। इससे

पहले जो लिस्ट आई थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के सब लोगों के नाम दिए गए थे कि किसके नाम पर कितना काला धन है और किस बैंक में जामा है। आप यह काला धन बंद करिए। आप इस देश को प्लास्टिक मनी से नहीं चला सकते हैं। आप यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। ...(व्यवधान)..... मैंने बिटकॉइन को तो उठाया था, लेकिन चला नहीं, बैन कर दिया। जिस देश की आबादी तीन परसेंट इनकम टैक्स देती हो, तो आप उस देश को प्लास्टिक मनी पर ले जाना चाहते हैं। आपने 67 हजार और बढ़ा दिए, जो अपनी इनकम टैक्स रिर्टन जाती है। इस 125 करोड़ के देश में आपने 67 हजार बढ़ा दिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपने अपने अधिकारियों को जितनी छूट दे रखी है, इसको बंद करिए। कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम जी भी कानून बनाते थे, लेकिन उनके बेटे पर ही वह कानून लग गया। मैं उनको कहता रहा कि यह मत समझो कि हम लोग ही सब कुछ हैं। अब वे कह रहे हैं कि हमारे बेटे पर कानून लग गया और भागे-भागे कोर्ट गए, ऐसे ही आपका हाल है। आप जितने भी फाइनैंन्स के बिल ला रहे हैं, उनमें किसी में सात साल की सज़ा है, किसी में पांच साल की सज़ा है और किसी में तीन साल की सज़ा है। अब तो आपने अधिकारी तक को सजा के लिए अधिकार दे दिया है कि वह किसी को भी पकड़ कर बंद कर दे। अब भ्रष्टाचार बढ़ गया और यह भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है। आप अपने मन से यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, यह तो चार गुना बढ़ गया है। कानपुर में GST कमिश्नर पकड़े गए हैं। आप कितने कमिश्नर पकड़ोगे? आपने सब काम अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया। अरुण जी वकील हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर

रहे हैं? हर जगह जेल-जेल, आपने रीयल एस्टेट में भी जेल कर दिया है। हमने तो इसको अपोज़ किया था, लेकिन लोग समझने लगे कि यह रीयल एस्टेट का आदमी है, यह तो बिल्डिंग बनाता है। हमारा सबसे ज्यादा विरोध शैलजा जी कमेटीज़ की मीटिंग्स में करने लगीं, तो हमने इनसे कहा कि हम बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। आप यह गलतफहमी मत रखिए, लेकिन रीयल एस्टेट ने देश में 12 करोड़ लोगों नौकरी दे रखी थी। उसने कोई पकौड़े वाली नौकरी नहीं दे रखी थी। अगर कोई एक प्लॉट बेचता था, तो एक साल तक उसके घर का खर्च चलता था। लोग पूछते थे कि क्या काम करते हो? शादी के समय पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है? आप कहेंगे कि लड़का पकौड़ा बेचता है, तो कोई शादी भी नहीं करेगा। यह कोई शादी के समय कहता कि मैं रीयल एस्टेट का काम करता हूं, तो कम से कम उसकी शादी तो हो जाती। आपने तो वह सब भी खत्म कर दिया।

आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर साल एक लाख महिलाएं kidnap की जाती हैं, लेकिन आपने 67 हजार की फिगर दी है। वे इसलिए kidnap की जाती हैं कि उनकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है। सबसे ज्यादा बिहार में जबरदस्ती शादी कराई जाती है। वहां पर तो लड़के की शादी भी जबरदस्ती लट्ठ के जोर पर कराई जाती है और लड़की की शादी भी लट्ठ के जोर पर कराई जाती है। ऐसे दूल्हे को पकड़वा दूल्हा कहा जाता है। लड़की का बाप जबरदस्ती लड़के को उठाता है और लट्ठ के दम पर शादी करवाता है, यह पकड़वा दूल्हा कहलाता है। यहां पर राम कृपाल

यादव जी बैठे हैं और हंस रहे है। राम कृपाल जी, आप तो खुद ही इसके गवाह रहे हैं और आपने बहुत सी ऐसी शादियां अटेंड भी की हैं।

(2W/LP पर जारी)

LP-BHS/5.30/2W

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : एक दिन हमें ही बता रहे थे, आज चुप हैं। अरे सत्यता बोलो, सत्यता बोलोगे तो लोग खुश भी होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि नीरज जी को भी बोलना है, हमारी पार्टी का टाइम सिर्फ 52 मिनट है और अभी 35 मिनट हो गए हैं, इसलिए कितना टाइम बचा हुआ है?

श्री नीरज शेखर : अभी आपके 17 मिनट बचे हुए हैं।

श्री नरेश अग्रवाल : इन्हें भी बोलना है। चूंकि अभी बोलना बहुत है और मेरे ख्याल से सभी लोग सुनना भी खूब चाहते हैं ..(व्यवधान)..

श्री मेघराज जैन : आप एक घंटा बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल : चलिए, जैन साहब रिटायर होने से पहले आपने पहली बार हमारी तारीफ तो की। हमने कहा, हमारी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हम तो एवर ग्रीन हैं, हम तो हर वक्त हँसते रहते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, न दौलत छाती पर ले जाओगे, न कोई चीज़ मिलने वाली है। आज जो संस्कार हो गए हैं, उनमें अगर बेटा साल में फोटो पर एक बार माला चढ़ा दे, तो समझ लीजिए कि वह बड़ा लायक बेटा हो गया है। बूढ़े-बूढ़ियों का जो हाल इस देश में हो रहा है, उसके लिए अब सोचना बंद कर दो। खैर, प्रमोद जी तो अकेले हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है,

फ़र्क नहीं पड़ता है। बूढ़े-बूढ़ियों का जो हाल हो रहा है, वृद्ध आश्रमों की जो हालत हो गई है, उस संदर्भ में तो जापान और चीन से ज्यादा बुरी हालत हिंदुस्तान की हो गई है। जब मैंने रेमंड के मालिक के बारे में सुना, तो रेमंड का सामान खरीदना बंद कर दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री नरेश अग्रवाल : मैं अभी खत्म कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि रेमंड के मालिक ने अपना सब-कुछ बेटे को दे दिया। ऐसा बाप, जिसने बेटे को 8,000 करोड़ रुपये दे दिए हों, उसको घर से निकाल दिया। उसे रहने के लिए मकान ही नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा कानून बनाइए कि अगर लड़का पैदा हुआ है, तो माँ-बाप की देख-रेख करने की उसकी जिम्मेदारी है। घर में चार रोटी हों और पाँच खाने वाले हों, तब अगर कोई भूखा रहेगा, तो माँ भूखी रहेगी, दूसरा कोई भूखा नही रहेगा। यह इस देश का कॉंसेप्ट है। आज जो स्थिति हो रही है, उसको देखने के लिए आप वृंदावन चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ क्या स्थिति है? अब ऐसा बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी होना शुरू हो गया है। यह जो स्थिति है कि लड़का जब तक कुँवारा अपना और शादी हुई तो जानिए गया, अब यह स्थिति आ गई है। महोदय, आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा बिल लाइए, जिससे देश के उन बुजुर्गों को, जिनकी सीनियर सिटिजन्स की उम्र हो गई है, उनको भी अपनी लाइफ की सिक्युरिटी मिल सके, सेफ्टी मिल सके और हिंदुस्तान जो था, वह फिर से वैसा ही हिंदुस्तान रहे। अगर गलतफहमी के शिकार रहोगे, तो नुक़सान होगा, क्योंकि हमने बड़ी-बड़ी सत्ताएँ परिवर्तित होती देखी हैं। हमने

चालीस साल के जीवन में उठा-पटक देखी है, जोड़-तोड़ करने में बड़े माहिर हैं हम। इस देश में "नरेश फॉर्मूला" भी चलता था। कल्याण जी की सरकार हमने ही उस समय बनवा दी थी, नहीं तो बनती नहीं, इसलिए आइए, बड़ा दिल करिए और अटल जी, जो कह गए थे, उस संदर्भ में लास्ट में इतना ही कहूंगा कि,

"छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।"

अटल जी ने ये दो लाइनें कही थीं। बीजेपी को अगर जिंदा किया तो अटल जी ने जिंदा किया, आडवाणी जी ने जिंदा किया। कम से कम इनके कहे शब्दों को ही याद कर लीजिए, आपका बहुत भला होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Naresh*ji* and thank you also for injecting a little bit of humour into the debate.

SHRI NARESH AGRAWAL: Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Well, hon. Members, I have to inform you that hon. Chairman has already said that Parties will not be given more time. Parties have to adhere to their time and, therefore, the first speaker should keep in mind that there will be a second speaker or third speaker.

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति जी, मेरी एक आपत्ति है। हम लोग इस चेयर की गरिमा नहीं गिरने देना चाहते हैं। आप बारम्बार कहते हैं कि चेयरमैन साहब ऐसा कह कर गए हैं, इस वजह से ऐसा करना है। आपके पास अधिकार हैं, इस देश में अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जब आपको नियमों में सब अधिकार दिये हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिए। आप चेयर हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I only quoted. ...(Interruptions)... No, no. I only quoted. ...(Interruptions)... अच्छा ठीक है, I only quoted. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : आप हमें अभी बिठा दीजिए, हम सब नियम अभी बदल देंगे। हम तो माहिर हैं नियम बदलने में। आप हमें बिठा दीजिए, हम सभी नियम अभी बदल देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was quoting the hon. Chairman. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Before that, Sir, I have a point for clarification. It is true that the time has been allocated for this debate and for the Budget. But, now, every time when the discussion is there, there are occasions when many minutes are lost for either Party because of interruptions. Even if that is not intentional, that happens. So, there is a spill-over effect.

(Contd. by RL/2X)

SHRI ANAND SHARMA (CONTD.): The second thing is that the debate will conclude on Wednesday as we have been informed. Now, on behalf of my party and on behalf of our colleagues in the Opposition...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. ...(Interruptions)... Please listen. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: We want to make one thing absolutely clear. Last time also it happened that the Government said that the debate would conclude the previous day and on the next day only the Government, the Prime Minister will speak. This will not be acceptable to us. If the reply is on Wednesday then the debate spills over to Wednesday. They will have to listen to some of us and then give the reply. It cannot be otherwise. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay. ...(Interruptions)... I have no objection to that. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: I am saying it in all seriousness. आप बताइए, कैसे होगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection to that.

श्री आनन्द शर्मा: आप चेयरमैन साहब को बता दें, वरना हाउस का सेंस ले लें। ...(व्यवधान).. ऐसे नहीं होगा। इतनी बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, उनका जवाब तो देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection to that. But, I am only saying that twelve hours is the time allotted. We sit up to 8.00 p.m. today and tomorrow up to 8.00 p.m. By then, twelve hours' time will be over. So, tomorrow by 8.00 p.m., the discussion has to be over because by that time it will be twelve hours.

SHRI ANAND SHARMA: No, no, Sir, we are very clear on that that if the reply is on Wednesday, then, I speak not only for myself but for the Opposition colleagues also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, this is for the Government... ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: It has to be then there. The Government is here; the Ministers are here. It has to be a level playing field. We do not want it and I have reasons for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood your point. ...(Interruptions)... I understood your point.

SHRI ANAND SHARMA: I will also be very transparent because the Government always has the advantage. Naturally, the President of the Ruling Party moves the Motion which is his right, very good. So, the message which goes to the people, and even in the media, the space gets

restricted for the criticism of the Government. On the final day, it is hundred per cent only of the Government and what others have to say in response, as the debate evolves, that cannot be frozen. And, that will not come. Then, the hundred per cent space goes one way. We will not accept that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; every party will get its due time. Now, Shri A. Navaneethakrishnan.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Hon. Deputy Chairman, I thank the hon. President for having delivered the speech in the Joint Sitting of both the Houses of Parliament. Since, I am hailing from Tamil Nadu, I would like to draw the kind attention of this august House; also of the Central Government and especially, of the hon. President to a burning issue because, now, the young students of Tamil Nadu are preparing for the Plus-II examinations. At the same time, they are worrying about the NEET examination. Now, as per law, NEET has been enforced. I would like to draw the kind attention of the Central Government and also kind attention of the hon. President to this issue.

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI BHUBANESWAR KALITA, in the Chair)

At the same time, I thank our senior Member, Shri T.K. Rangarajan who has done a wonderful and a brilliant thing and, that is, writing to the

office of the President to know about the status of the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature seeking exemption from NEET. For that letter written by our hon. senior Member, Shri T.K. Rangarajan, the President's office has given a reply that the President's Office did not receive the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature. Now, I want to raise this issue and I would also like to draw the kind attention of the Parliamentary Affairs Minister to this because this is concerning about the powers in the jurisdiction of the Central Government and also the exclusive jurisdiction and domain of the hon. President. My humble submission would be my reading of Articles 52, 53, 73, 74 and its provisos, Articles 246 & 254 of our Constitution.

(CONTD. BY KR/2Y)

KR/AKG/2Y/5.40

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD.): It is very clear. I am not accusing the Central Government. But I am urging the Central Government to take note of the mental agony of our Tamil Nadu students which they are undergoing. Now from the reply given by the hon. President of India to our colleague, Shri T.K. Rangarajan it is very clear. The Bill passed by the Tamil Nadu Legislature unanimously is reply to the will of the people of Tamil

Nadu. The Bill has been passed not without any legislative competency. The Concurrent List empowers the Tamil Nadu Legislature to pass a law on the subject of education. Though the Tamil Nadu Legislature has the jurisdiction, competency to pass a law which is included as one of the subjects in the Concurrent List, of course, that law now passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly is a rebuttal to the law passed by the Indian Parliament, namely, the Indian Medical Council Act, Section 10 (c). To resolve the repugnancy, there is a provision in the Constitution; it is unknown to anybody but it is known to the Central Government. I request the Central Government, and urge the Central Government to kindly go through it. It is my humble request only to save the young students of Tamil Nadu. Last year a bright young girl had committed suicide. It attracted the attention of the whole world because she had secured more marks, but she did not secure more marks in NEET. It is a very sensitive matter and involves future of young students.

In the light of my reading of the Indian Constitution, what now appears is the inaction on the part of the Central Government and inaction on the part of the hon. President. It causes violation of the Indian Constitution. How? What is vested with the hon. President is the Executive power of the Union

of India. So, the hon. President is the head of the Executive of the Union of India. So, he discharges the Executive powers of the Union of India under the seal of the President. As per Article 74 the aid and advise of the Council of the Ministers come into the picture only with regard to the matters of Executive powers of the Union. So, for the executive powers of the Union alone the President is bound by the aid and advise of the Council of Ministers headed by the hon. Prime Minister. But this is a matter in which the Tamil Nadu State Legislature has enacted a law. It concerns the subject included in the Concurrent List. So, legislative competence can't be faulted. It has got full competence to enact the law that too unanimously passed.

Now, as per Article 254 "Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States, clause (2) says, "where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to the matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

In this connection, I would like to draw the kind attention of the Central Government to clause 2, "Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting any time any law with respect to the same matter including a law adding to amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State."

(Continued by 2Z/KS)

KS/2Z/5.45

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (contd.): So, my humble submission would be, the power conferred upon the hon. President under article 254 is not within the purview of 'aid and advice of the Council of Ministers headed by the hon. Prime Minister'. It is an independent power vested with the hon. President because the Legislature's power, especially those of the Tamil Nadu Legislature, cannot be exercised by the Central Government. That is very clear. So, the Central Government's power is only executive; it is not judicial or legislative and, there too, the legislative power of the State Government, namely the Government of Tamil Nadu, cannot be taken over by the Central Government. So, in what is being contemplated, according to me, with due respect to the Office of the hon. President, the hon. President has no say here. If the Bill has been reserved for his assent, he

must give assent to it. Then, it is up to the Central Government to introduce another law to amend merely to do anything else in the Parliament. So, my humble submission would be, the power of the Tamil Nadu Legislative Assembly has been now taken over; it has been bypassed, ignored; and, further, by keeping the Bill that has been reserved for the assent of the President by the Central Government, the Parliament has also been bypassed. So, my submission would be that the Concurrent List is not a mere paper. It doesn't mean that the law passed by the State Legislature can be kept with the Secretaries of the Central Government without forwarding it even to the President of India. My humble submission is that the entire Concurrent List now stands deleted because even as per Article 254, if there is any repugnancy, then the Central law would prevail. That doesn't mean that you can ignore the entire Concurrent List; by deleting the Concurrent List, you are taking away the powers of the State Governments. This is a very serious issue. You are violating the very basic features of the Constitution. Now, even the Court cannot decide upon a law competently passed by the Legislature or the Central Government. Now, the Tamil Nadu Government has passed a law seeking exemption from appearing in NEET Examination. If it is repugnant to the Central law, it is permissible under law;

wherever repugnancy arises, a Bill must be sent to the President for his assent and the President has to give his assent; only then, it must be taken over by the Central Government to consider whether a Bill could be introduced to amend, vary or to nullify the Act passed by the Tamil Nadu Legislature. This is the scheme contemplated in our Constitution, but you are bypassing the Parliament, the Tamil Nadu Legislature and also the Office of the President of India. The principle of seeking the aid and advice of Council of Ministers, headed by the hon. Prime Minister is not applicable to the law passed by the Tamil Nadu State Legislature, that too, on a subject that is included in the Concurrent List. So, the repugnancy can be resolved only by the Parliament passing the law, not by withholding the files in Central Government offices. I am not accusing or blaming the Central Government. This is the practice that has been going on since Independence. So, I cannot blame anybody. We have to blame our own fate! So, my submission is that we don't want to witness suicides of young students in this current academic year. Parliament alone can pass the law, not the Central Government or the State Government. So, the Tamil Nadu Legislature has unanimously passed a valid law. It is entitled to pass a law which is repugnant to the Central law.

(CONTD. BY RSS/3A)

RSS/3A/5.50

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD): Now, the Tamil Nadu Legislature has passed a law which is repugnant to the Central law. It has no legislative jurisdiction and competency. So, having passed a Bill,-- it is only an administrative procedure--, even now, I humbly urge the Central Government to forward the Bill to the hon. President, and the hon. President must bow to give the assent, and then only, the Central Government can examine the issue. Its jurisdiction ends there as soon as the Bill is introduced here, to vary, amend, abrogate or to do anything. Then, it is a matter within the domain or jurisdiction of the Parliament. Parliament alone can say that the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature is not valid. The Concurrent List is now deleted by the Central Government which is a basic feature of the Constitution. Without a Concurrent List, our Constitution cannot exist. The BJP is full of intellectuals. There is no doubt about it. By force of habit, all the files containing Bills or proposals which will be repugnant to the Central Government, are kept aside, without doing anything, or, for which assent is refused. My humble submission would be, it is a very, very serious matter pertaining to the young people of Tamil

Nadu. Long back, in our State, the entrance examinations have been abolished by passing an Act. That Act has been upheld by the Supreme Court. Of course, now, the Parliament has enacted Sections 10C, 10D of the Indian Medical Council Act. But, at the same time, I would like to draw your attention to the fact that the Central Government has announced that six colleges would be established in Tamil Nadu, but they are yet to be established. For AIIMS, NEET is not applicable. AIIMS is conducting their own examinations. AIIMS is at a higher level. Students joining the AIIMS are very bright and brilliant. Likewise, NEET is not the deciding test to assess the capability, intelligence, hard work, or, the aptitude for service in the rural areas. Learning process is a continuous one. By one single test, you cannot assess the capability of the student. That is not the right method. One can acquire knowledge slowly. What is the concept of inclusive growth? If a student is very poor, he should not be left to be poor forever! That is not the concept of the inclusive growth. Social justice is being denied to the poor students. The competitive edge is available to the urban students, though, of course, thanks to our Amma, she has protected the poor people, and 69 per cent reservation is in force. So, of course, in spite of the NEET, 69 per cent reservation is in force, is being implemented. But, even in 69 per cent

reservation, only the rich, urban people of those respective communities are enjoying the benefits. So, the first generation students hailing from poor, rural background, are not able to reach the medical colleges. That is why, those students who have studied with the help of the Government quota at a lesser cost, as soon as they become doctors, they never go to the rural areas. They confine themselves to the multinational hospitals, corporate hospitals. So, my reading of the constitutional provisions in the Articles is that the hon. President has exclusive domain, jurisdiction to give the assent. Even with due respect to the office of the hon. President, the hon. President is bound to give the assent to the Bill now passed by the Tamil Nadu Assembly because this Bill is to protect the poor rural students. Now, my humble submission would be, don't bypass the Parliament; don't bypass the Tamil Nadu Legislative Assembly; don't delete the Concurrent List from the Constitution. You are violating the principle of the State autonomy, and you are violating the basic features of the Constitution. I am not accusing anybody. I am not blaming anybody. If any law is repugnant to the Central law, it will either be kept under the drawers of the officers or it will not see the light of the day.

(contd. by 3B/KGG)

KGG-PSV/3B/5.55

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (contd.): Or, it has never seen the light of the day. I have gone through the case law to an extent. Subject to correction, I would say that the basis of aid and advice given by the Council of Ministers are annullable in the judicial review. The judicial review, which is a basic feature of the Constitution, you are now violating. So, Parliament, the Tamil Nadu Legislative Assembly, the judicial review, the powers of the President, everything is now violated by keeping the files in the drawers of the office of the Central Government.

My humble submission would be, if there is anything on the part of the Government, it is reflected on the President. The President himself, according to me, is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers. It is an independent jurisdiction conferred upon him. This is my humble opinion because what I quoted is a State law which is in the Concurrent List, forwarded under Article 245. Then, the President has to give his assent. The jurisdiction, of course, is vested with the Central Government to introduce a Bill or to deal with that law. Before that, the Central Government can't destroy the Constitution, the legislative powers, the Parliament, the judicial review power as also the office of the President.

Now, in Tamil Nadu, young people are agitated because they are not capable of preparing for two examinations simultaneously—one for the NEET and another for the State Board. They are suffering; they are undergoing mental agony.

I very humbly urge the hon. President, through this House, to kindly consider and give his assent as early as possible. Also, I very, very humbly urge upon the Central Government, led by hon. Prime Minister, to consider and give a favourable advice to the President to give assent to the Bill so as to see to it that the law is enforced in Tamil Nadu. Tamil Nadu may please be given an exemption from NEET which is now warranted, which is now necessary.

I thank the President for his Address. I also thank the Central Government for the wonderful schemes they have introduced. Definitely, there will be a New India. There is no doubt about it. ...(Interruptions)... I hope, the Bill passed by the Tamil Nadu will be accepted by the Government. I hope, the Central Government will not reverse it.

I thank the Chair and I also thank the hon. Members. Thank you, Sir.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Sukhendu Sekhar Ray.

(3सी/वीएनके पर जारी)

Pp 216 onwards will be issued as supplement.